payment to G.D.P. in 1992-93 is not available as the amount of GDP in 1992-93 can not be estimated precisely at this stage.

Modernisation of airports during the Eighth Plan period

*24. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether the National Airports Authority propose to modernise various airports in the country during the Eighth Plan period;

(b) if so, what alocations have been made therefor;

(c) whether Government have allocated funds for the modernisation of four international airports at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras;

(d) if so, what are the reasons for not allocating funds for other airports in the country; and

(e) what steps Government propose to take to modernise all airports in the country?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) The allocation for Civil Aviation Sector during the Eighth Plan has not been finalised.

(c) and (d) Pending finalisation of the Eighth Plan, an outlay of Rs. 99.34 crores has been made for development of the airports in Delhi, Bombay, Calcutta and Madras in 1992-93. Likewise, for other airports, an outlay of Rs. 126.02 crores has been made for the year 1992-93.

(e) Modernisation of airports is a continuing process envisaging expansion and/or provision of new services, improvement of air traffic control services, navigational aids and passenger facilitation equipment.

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधियों का आबंटन

*25. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक द्वारा आबंटित धनराशि में से कम धनराशि उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस वर्ष के लिए आबंटित पूरी धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विश्व बैंक परियोजना को 1982 में स्वीकृत किया गया था जिसके अधीन 304 मिलियन अमरीकी डालर (382.87 करोड़ रुपये) की ऋण सहायता में, 1983-85 की अवधि के दौरान चुनिंदा राज्यों में चुनिंदा ग्राम विद्युतीकरण निगम वित्त पोषित स्कीमों के लिए अपेक्षित प्रमुख सामग्री तथा उपस्कर के वित्त-पोषण हेतु स्कीम को शामिल किया गया था। परियोजना को जून, 1988 में बन्द कर दिया गया था । विश्व बैंक द्वारा परियोजना के लिए विशेष रूप से कोई भी राज्यवार आबंटन नहीं किया गया था। इस स्कीम के अधीन उत्तर प्रदेश द्वारा 57.36 करोड़ रुपये की राशि का समुपयोजन किया गया था । तथापि, इस समय ग्राम विद्युतीकरण के लिए कोई विश्व बैंक पोषित परियोजना प्रचालनाधीन नहीं है।